

मैसूर राज्य

हैदरअली ने मैसूर राज्य में अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था, और उस समय मैसूर का शासक कृष्ण राज वाडियार था। किंतु मैसूर राज्य की वास्तविक बागडोर उसके प्रधानमंत्री नंदराज के हाथ में थी।

हैदरअली ने बाद में अपनी सैनिक योग्यता और स्वामी भक्ति के बल पर धीरे-धीरे नंदराज का विश्वास प्राप्त कर लिया और 1755AD में नंदराज के द्वारा हैदरअली को डिंडीगल जिले का फौजदार नियुक्त कर दिया।

Dendigal के फौजदार के पद पर रहते हुये Haider Ali ने आस-पास के प्रदेशों में लूटमार करके, न केवल उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया था अपितु डिंडीगल में उसने हथियारों का भी बहुत बड़ा जखीरा (शस्त्रागारों) भी इकट्ठा कर लिया और उसने अपनी सैनिक शक्ति में काफी वृद्धि करली।

बाद में नंदराज की मृत्यु हो जाने के बाद 1761 AD में Haider Ali ने Mysore के शासक कृष्ण राज वाडियार को कैद करके वह स्वयं मैसूर का वास्तविक शासक बन गया।

दक्षिण भारत में हैदरअली के नेतृत्व में बढ़ती हुई मैसूर की शक्ति से विशेष रूप से अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम अपने हितों के लिये हानिकारक मानते थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी की अंग्रेज सरकार दक्षिण भारत में अपने राजनैतिक प्रभुत्व का विस्तार करना चाहती थी, जिसके फलस्वरूप ही अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य निम्नलिखित 4 युद्ध लड़े गये।

First Anglo-mysore war (1766-69)

- प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास प्रेसिडेंसी का अंग्रेज गवर्नर एण्डरसन था।
- 1765 AD में हैदराबाद के तत्कालीन शासक निजामअली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हैदरअली के विरुद्ध एक समझौता हुआ जिसके अनुसार

इन दोनों शक्तियों ने मिलकर मैसूर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु बाद में मराठों भी हैदरअली के विरुद्ध इस गुट में सम्मिलित हो गये, इस प्रकार 1766 AD में हैदरअली के विरुद्ध इन तीनों का एक त्रिगुट बन गया।

- प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध का सबसे प्रमुख और तत्कालीन कारण मद्रास प्रेसिडेंसी की अंग्रेज सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप करना माना जाता है।
- प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान स्मिथ ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति था।
- किंतु प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में सर्वप्रथम मैसूर पर पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा सेना द्वारा आक्रमण किया गया था।

किंतु हैदरअली ने कूटनीति का प्रयोग करते हुये पेशवा माधवराव को 35 लाख रुपये देकर इस युद्ध से अलग कर दिया। तथा बाद में वह हैदराबाद के निजाम को भी धर्म का वस्ता देकर इस युद्ध से तटस्थ करने में सफल हो गया।

मराठों और हैदराबाद के निजाम को तटस्थ करने के बाद हैदरअली ने 1768 AD में मंगलौर पर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से लिया, तथा इसके बाद उसने मद्रास का घेरा डाल दिया था। किंतु अन्ततः मद्रास एंडरसन प्रेसिडेंसी के गवर्नर एंडरसन की प्रार्थना पर 1769 AD में हैदरअली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि हो गई जिसके मुख्य प्रावधान सग्रांकित थे।

1. हैदरअली और अंग्रेज दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुये प्रदेश वापस लौटा दिये।
2. करूर का जिला जो हैदरअली द्वारा कर्नाटक के नवाब से छीन लिया गया था वह हैदरअली के पास ही रहने दिया गया।
3. यदि कोई तीसरी शक्ति इन दोनों पर आक्रमण करती है तो उसके विरुद्ध वे एक-दूसरे की मदद करेंगे।

इस प्रकार इस मद्रास की संधि के साथ ही 1769 AD में प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदरअली द्वारा निर्धारित की गई थी और वह प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में विजेता रहा था, किंतु इसके बावजूद भी उसने मद्रास की संधि में बहुत ही उदार शर्तें निर्धारित की थी।

इसका कारण यह माना जाता है कि हैदरअली हैदराबाद के निजाम और मराठों की तुलना में अंग्रेजों को अधिक विश्वसनीय मित्र मानता था और वह उनके साथ स्थायी रूप से मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहता था।

Second Anglo-Mysore war 1780-84

- द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर मैकार्टनें था।
- 1771 AD में जब पेशवा माधवराव द्वारा मैसूर पर आक्रमण किया गया, तब मद्रास की संधि के अनुसार जब अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध हैदरअली की कोई मदद नहीं की, तब हैदरअली के अंग्रेजों के साथ सम्बन्ध काफी खराब हो गये, और वह अंग्रेजों से इसका बदला लेना चाहता था, इसी समय अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण अंग्रेजों के मराठों के साथ भी सम्बन्ध काफी खराब थे। इसके साथ ही हैदराबाद का तत्कालीन शासक निजामअली भी अंग्रेजों से सख्त नाराज था, क्योंकि 1765 AD की संधि के अनुसार उत्तरी सरकार के चार जिलों के बदले में (7 लाख रुपये) वार्षिक जो निजाम के देना तय हुआ था, उसे अंग्रेजों ने बंद कर दिये।

इन सबका लाभ उठाकर हैदरअली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया। जिसके पीछे हैदरअली का मुख्य उद्देश्य भविष्य में अंग्रेजों के साथ होने वाले युद्ध में वह इन दोनों शक्तियों को तटस्थ बना देना चाहता था।

- द्वितीय आगल मैसूर युद्ध का सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण 1779 AD में अंग्रेजों द्वारा माही (mahe) की फ्रांसीसी फैक्ट्री पर अपना अधिकार कर लेना, जिसे हैदरअली अपना संरक्षित प्रदेश मानता था।
- द्वितीय आगल-मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना के दो मुख्य सेनानायक सर अपरकूट और जनरल बैली थे।
- द्वितीय आगल-मैसूर युद्ध के दौरान चार अग्रलिखित लड़ाईयाँ लड़ी गईं।

(1) आरनी का युद्ध

(2) पोर्टोनोवा का युद्ध

(3) पोलिलोर का युद्ध

(4) सौलिगेर का युद्ध

- (1) **आरनी का युद्ध :-** 1780 AD में जनरल बैली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और टीपू के नेतृत्व में मैसूर सेना के मध्य हुआ, जिसमें टीपू द्वारा अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया गया और जनरल बैली सहित बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिकों का टीपू द्वारा वध करवा दिया गया।

आसी के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय का बदला लेने के लिये युद्ध में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया और उसने जनरल आयरकूट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना बंगाल से दक्षिण भारत में भेजी।

- (2) **Porto-Nova का युद्ध :-** जनरल आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और हैदरअली के मध्य 1781 AD में Porto-Nora की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई। जिसमें हैदरअली की पराजय हो गई।
- (3) **Polilor का युद्ध :-** किंतु Porto Nora के युद्ध के बाद 1782 AD में हैदरअली और जनरल आयरकूट के बीच पोलिलोर का युद्ध और सौलिंगेर का युद्ध लड़ा गया। ये दोनों युद्ध अनिर्णायक रहे थे।

किंतु 1782 AD में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदरअली की मृत्यु हो जाने के कारण टीपू मैसूर का शासक बना और उसने भी इस युद्ध को जारी रखा। और 1783 AD में टीपू को अंग्रेजों के विरुद्ध इस युद्ध में एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जब जनरल मैथ्यूज की कमान में एक अंग्रेजी सेना को पराजीत करके जनरल मैथ्यूज को कैद कर लिया गया। किंतु टीपू स्वयं इस युद्ध को लम्बे समय तक चलाने के पक्ष में नहीं था। और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर में कार्टने भी इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहता था।

अतः 1784 AD में टीपू और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि हुई जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे –

1. दोनों एक-दूसरे के जीते हुये प्रदेश वापस लौटा देंगे।
2. दोनों एक-दूसरे के युद्ध-बन्धियों को वापस लौटा देंगे।

इस प्रकार 1784-AD में इस मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हो गया।

III Anglo-Mysore war (1790-92)

- Third Anglo-Mysore war के समय लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था।
- टीपू जो इस समय मैसूर का शासक था, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में उनका सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था, और वह भारत से अंग्रेजी सत्ता के समाप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस, टर्की, काबुल, आदि विदेशी शक्तियों से भी सैनिक मदद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, जिसे कार्नवालिस भारत में ब्रिटिश राज्य के हितों के लिये हानिकारक समझता था। अतः उसने टीपू की शक्ति को कुचल देने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध मैसूर राज्य में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। और जुलाई 1789ADमें उसने टीपू के विरुद्ध हैदराबाद के तत्कालीन निजामअली और मराठों के साथ एक समझौता कर लिया था, जिसके

अनुसार यह निश्चय किया गया था कि मैसूर विजय के बाद तीनों (निजाम, मराठे, अंग्रेज) मैसूर राज्य को आपस में बराबर-बराबर बाँट लेंगे।

- III आंग्ल-मैसूर युद्ध का सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण टीपू द्वारा 1790 AD में ट्रावनकोर (केरल) राज्य पर आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि ट्रावनकोर पर आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि ट्रावनकोर का शासक अंग्रेजों के द्वारा उकसाये जाने पर टीपू के विद्रोही सरदारों को अपने यहाँ शरण दे रहा था और मैसूर राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा था।
- III आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश सेना कार्नवालिस का नेतृत्व जनरल मीडोज के हाथों में थी। किंतु जब जनरल मीडोज टीपू के विरुद्ध कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका तो स्वयं कार्नवालिस ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था।
- और उसके द्वारा टीपू के मैसूर राज्य के अधिकांश किलों पर अधिकार स्थापित कर लिये जाने के बाद जब वह मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंग-पट्टम तक पहुँचने में सफल हो गया, तब टीपू के प्रस्ताव पर 1792 AD को टीपू और कार्नवालिस के मध्य एक संधि हुई जिसे ही श्रीरंगपट्टम की संधि (Treaty of Seringapatana के नाम से जाना जाता है। और इटन संधि के साथ ही 1792 AD में Third Anglo-Mysore war समाप्त हो गया।
- यद्यपि इस समय कार्नवालिस संपूर्ण मैसूर राज्य को जीतकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकता था। लेकिन जब कार्नवालिस द्वारा संपूर्ण मैसूर राज्य पर अधिकार न करने के आलोचना की गई तो कार्नवालिस ने यह कहकर अपने इस निर्णय को उचित ठहराया था कि “मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाये बिना अपने शत्रु (टीपू) को काफी हद तक दुर्बल कर दिया”।

- श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार मैसूर राज्य को जो भू-भाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था उसमें मुख्यतः Dendigal डिंडीगल, बारामहल दो जिसे शामिल थे।

इसी बारामहल जिले में 1792 AD में कर्नल रीड द्वारा रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी इस समय टॉमस मुनरो कर्नल रीड का सहायक था, और इसी टॉमस मुनरो कर्नल हीड़ का सहायक था, और इसी टॉमस मुनरो द्वारा बाद में जब वह मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर (1820 AD में) नियुक्त हुआ तब उसने संपूर्ण मद्रास प्रांत में इस रैयतवारी प्रथा को लागू कर दिया था।

Treaty of Seringapatam कब, किनके मध्य और महत्व को स्पष्ट कीजिये।

श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 AD में Tipu Sultan और Lord Cornwallis के मध्य हुई, इसमें मुख्य प्रावधान अग्रांकित हैं।

1. Tipu द्वारा Mysore का आधा राज्य अंग्रेजों को सौंप देना पड़ा। जिसे बाद में समझौते के अनुसार अंग्रेजों, हैदराबाद का निजाम और मराठों ने आपस में बाँट लिया था।
2. टीपू द्वारा 30 लाख पौण्ड (3 करोड़ रुपये) युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को देने पड़े। जब तक टीपू इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर देगा, तब तक टीपू के दो पुत्र अंग्रेजों के पास बन्धक के रूप में रहेंगे।
3. Importance of Seringapatam treaty :- इस प्रकार श्रीरंगपट्टम की संधि के फलस्वरूप मैसूर राज्य सैनिक और आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों द्वारा काफी हद तक दुर्बल बना दिया गया।

Fourth Anglo-Mysore war/1799 AD चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध

IV आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वैसेजली गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था।

- यद्यपि टीपू की III आंग्ल-मैसूर युद्ध में पराजय हो गई और उसके आधे राज्य पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, किंतु इसके बावजूद भी टीपू अपनी पराजय को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं था। और अंग्रेजों से

अपनी इस पराजय का बदला लेने के लिये उसने अपनी सैन्य शक्ति का पुनः संगठन करना प्रारंभ कर दिया था। तथ एक बार पुनः उसने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस और टर्की से सैनिक मदद प्राप्त करने का प्रयास किया था।

- लॉर्ड वेलेजली भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहता था, टीपू द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की मदद प्राप्त करना वेलेजली उचित नहीं मानता था।

अतः उसने सबसे पहले टीपू के विरुद्ध ही अपनी आक्रामक नीति का अनुशरण किया। और मार्च 1799 AD में टीपू के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप ही Fourth Anglo mysore युद्ध प्रारंभ हुआ।

- चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना के मुख्य सेनापति लॉर्ड वेलेजली का छोटा भाई आर्थर वेलेजली, जनरल स्टुअर्ट हेरिस थे।
- चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान अग्रलिखित दो मुख्य लड़ाईयाँ लड़ी गईं।
 1. **सिदासीर क युद्ध :-** यह लड़ाई जनरल (स्टुअर्ट) और टीपू के मध्य 5 मार्च 1799 AD में हुआ। जिसमे टीपू की पराजय हो गई।
 2. **मालवैली का युद्ध :-** यह युद्ध April, 1799AD को जनरल हेरिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और टीपू के बीच में हुआ था। जिसमें भी टीपू की पराजय हुई और इस युद्ध के बाद टीपू को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में शरण लेनी पड़ी, जिसका घेरा डालकर अंग्रेजों द्वारा मई 1799 AD में श्रीरंगपट्टम पर अधिकार कर लिया गया और टीपू यहीं पर अंग्रेजों के साथ युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया।
- टीपू की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेजली द्वारा मैसूर राज्य का अधिकांश भाग ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। तथा मैसूर राज्य का कुछ भाग मैसूर के पुराने उडियर को सौंप कर उसे मैसूर का शासक स्वीकर कर लिया और कृष्ण राज बहादुर उडियार ने 1799 AD में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया।

पंजाब

सिख-आंग्ल सम्बन्ध

रणजीतसिंह का अंग्रेजों के साथ सम्बन्ध :-

- रणजीत सिंह के द्वारा पंजाब में एक स्वतंत्र सिक्ख राज्य की स्थापना कर देने के पूर्व मुगल साम्राज्य की दुर्बलता के परिणाम स्वरूप पंजाब में घोर राजनैतिक अव्यवस्था थी, और अफगानों तथा मुगल अधिकारियों द्वारा पंजाब की जनता पर जो अत्याचार किये जाते थे उसके कारण सिक्ख सरदारों ने 100-100 व्यक्तियों को मिलाकर अनेक राजनीतिक दलों का गठन कर लिया। बाद में 1747 AD में इन सब छोटे-छोटे सिक्ख दलों को मिलाकर जस्सासिंह कलाल के नेतृत्व में उन्होंने अपना दल खालसा के नाम से एक बड़ा राजनैतिक संगठन स्थापित कर लिया था।
- बाद में दल खालसा द्वारा पंजाब में 1753 AD में राखी प्रथा प्रारंभ की जिसके अनुसार दल खालसा द्वारा प्रत्येक गांव से उसकी उपज का 1/5 भाग वसूल किया जाता था, जिसके बदले में दल खालसा द्वारा उस गांव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया जाता था।
- बाद में दल खालसा द्वारा सिक्खों को 12 अलग-अलग जत्थों में बाँट दिया गया था, जिन्हें 'मिसल' कहा जाता था।

प्रत्येक मिसल का एक अध्यक्ष होता था जो निर्वाचित होता था, किंतु बाद में मिसल के अध्यक्ष एक शक्तिशाली शासक के रूप में परिवर्तित हो गये।

इस प्रकार रणजीतसिंह के पूर्व पंजाब 12 छोटे-छोटे सिक्ख राज्यों (मिसलों) में बँटा हुआ था। ये 12 मिसलें निम्न थी -

मिसल	संस्थापक
आहलूवालिया	जस्सा सिंह आहलूवालिया
सिंहपुरिया	कपूर सिंह नवाब
कन्हैया	जगसिंह

भंगी (भांगी)	हरिसिंह
शुकरचाकिया / शकर चकिया	चरतसिंह
रामगढ़िया	जस्सासिंह रामगढ़िया
निशानवालिया	सरदार संगत सिंह
करोड़ सिधिया	बघेरसिंह
दल्मवालिया	गुलाबसिंह
नकई	हीरासिंह
शाहिदी	बाबा दीप सिंह
फूलकियाँ	फूलसिंह

- रणजीत सिंह क जन्म 2 नवम्बर 1780 AD में हुआ था, उनके पिता शुकरचकिया मिशल के अध्यक्ष थे उनका नाम महासिंह था। गुजराँवाल उनकी राजधानी थी।
- 1792 AD में महसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद रणजीत सिंह का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। किंतु इस समय रणजीत सिंह वयस्क नहीं था। अतः उसका दीवान लखपतराय उसका संरक्षक नियुक्त हुआ।
- रणजीतसिंह के गद्दी पर बैठने के समय सिक्ख राज्य भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बटों हुआ था।
- अधिकांश सिक्ख राज्य सतलज नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित था जबकि कुछ सिक्ख राज्य जैसे— नाभा, पटियाला, कैथल, जींद में सतलज नदी के पूर्व में स्थित थे। इन चारों सिक्ख राज्यों को ही sikhassatley state के नाम से जाना जाता था।

ये चारों सिक्ख राज्य फूलकियाँ मिशल के माने जाते थे।

- रणजीत सिंह इन सभी सिक्ख राज्यों को जीतकर पंजाब में एक संगठित और स्वतंत्र सिक्ख राज्य की स्थापना करना चाहता था, और 1798 AD में Ranjit Singh ने अहमदशाह अब्दाली के पौत्र जमानशाह द्वारा पंजाब पर आक्रमण किये जाने के दौरान उसकी जो मदद की थी, उसके फलस्वरूप जमानशाह ने लाहौर रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार रणजीतसिंह की पहली राजनैतिक उपलब्धि 1798AD में लाहौर उसे प्राप्त हो जाना।

- इसके बाद 1802 AD में रणजीतसिंह ने अमृतसर को भी जीतकर अपने अधिकार में कर लिया।
- किंतु जब रणजीतसिंह ने सतलज नदी के पूर्व में स्थित सिक्ख राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया तब अंग्रेजों द्वारा उसका कडा विरोध किया था, क्योंकि इन सिक्ख राज्यों को अंग्रेज अपना संरक्षित प्रदेश मानते थे।

किंतु जब 1808 AD में स्पेन प्रायद्वीप के युद्ध में असफल हो जाने के बाद नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो गया। और भारत पर नेपोलियन के आक्रमण की संभावना, समाप्त हो गई, तब तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लॉर्ड मिंटो ने रणजीतसिंह को सतलज नदी के पूर्व में स्थित सिक्ख राज्यों पर आक्रमण न करने की (स्पष्ट धमकी दी थी। और इन राज्यों पर रणजीतसिंह के आक्रमणों को ब्रिटिश राज्य पर आक्रमण किया जाना माना जायेगा

- लॉर्ड मिंटो ने 1809 AD में रणजीत सिंह को चार्ल्स मेटकॉफ के माध्यम से एक संधि करने, 25 अप्रैल, 1809 AD को विवश किया जिसे ही treaty of Amritsar के नाम से जाना जाता है। इस संधि के माध्यम से रणजीतसिंह व अंग्रेजों के मध्य सतलज नदी सीमा रेखा बन गई।

Treaty of Amritsar (अमृतसर की संधि) रणजीत सिंह और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के बीच अप्रैल 25, 1809 AD को हुई, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे।

1. अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित जो 45 परगने रणजीत सिंह के अधिकार में थे, उन पर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया।
2. सतलज नदी के पूर्व में स्थित सिक्ख राज्यों पर (सिक्ख सतलज स्टेट्स) रणजीत सिंह आक्रमण नहीं करेगा, जबकि सतलज नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित सिक्ख राज्यों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

3. भविष्य में रणजीतसिंह और अंग्रेज दोनों परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखेंगे।

महत्व

इस प्रकार अमृतसर की संधि से सतलज नदी रणजीतसिंह और अंग्रेजों के मध्य स्थायी सीमा रेखा बन गई।

- अमृतसर की संधि के बाद जब अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित सिक्ख राज्यों में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना समाप्त हो गई, तब रणजीतसिंह ने 1809 AD में सर्वप्रथम कांगडा, 1813 AD में अटक, 1818 AD में मुल्तान, 1819 कश्मीर और 1823 में पेशावर को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया।

रणजीतसिंह का प्रशासन/शासन-व्यवस्था

- रणजीत सिंह द्वारा सिक्ख राज्य के लिये जो शासन व्यवस्था गठित की गई उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी। (A) केन्द्रीय शासन केन्द्रिय सरकार में रणजीतसिंह द्वारा निम्न पाँच मंत्री नियुक्त किये गये :-
 - (1) **वजीर :-** (प्रधानमंत्री होता था, और उसने इस पद पर ध्यान सिंह डोगरा को नियुक्त किया था और उसे 'राजा कला' की उपाधि दी थी।
 - (2) **विदेश मंत्री :-** इस पद उसने फकीर अजीज-उद्दीन/ को नियुक्त किया। (फकीर अजीजुद्दीन)
 - (3) **वित्तमंत्री :-** इस पद पर उसने पहले भवानीदस और उसके बाद गंगराम और दीनानाथ को नियुक्त किया।
 - (4) **ग्रहमंत्री :-** यह वास्तविक रूप में शाही परिवार से सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष होता था। और इस पद उसने नौरुद्दीन को नियुक्त किया।
 - (5) **सेनापति :-** इस पद उसने पहले दीवान मोखमसिंह, दीवान चन्द और उसके बाद हरिसिंह नलुवा को नियुक्त किया गया। (B) प्रान्तीय शासन रणजीत

सिंह द्वारा सिक्ख राज्य को निम्न चार प्रांतों में विभाजित किया :- 1. मुल्तान 2. लाहौर 3. पेशावर 4. काश्मीर

- प्रांत को सूबा कहा जाता था और सूबा का अध्यक्ष नाजिम कहलाता था।
- रणजीतसिंह द्वारा प्रत्येक प्रांत या सूबों को अनेक प्रांत/सूब किल जिलों में विभक्त किया, जिन्हे तालुका कहा जाता था जिले का अध्यक्ष कारदार कहलाता था।
- प्रत्येक जिले या तालुका में 50 से लेकर 100 गाँव सम्मिलित थे, और प्रत्येक गांव का प्रशासन चलाने ग्राम पंचायत के लिये एक पंचायत होती थी।

(C) **सैनिक व्यवस्था :-** रणजीत सिंह के द्वारा 75,000 सैनिकों की एक अत्यंत शक्तिशाली सेना का गठन किया गया था। जिसे अंग्रेज इंग्लैण्ड के शासक फ्रोमवैल की लोह सेना Iron Army से करते थे, जो निम्न दो भागों में विभाजित की गई थी। (1) फौज-ए-खास (2) फौज-ए-बेकवायद

(1) **फौज-ए-खास** रणजीत सिंह की मुख्य सेना फौज-ए-खास थी, जो तीन भागों में विभाजित थी -

(A) **पैदल सेना :-** पैदल सेना का अध्यक्ष पैदल व भूरा रणजीत सिंह ने जनरल वन्तूरा नामक फ्रांसीसी जनरल को बनाया।

(B) **घुड़सेना :-** घुड़सवार सेना का अध्यक्ष अलार्द नामक फ्रांसीसी जनरल को बनाया।

(1) **तोपखाना :-** तोपखाना का अध्यक्ष जनरल कोर्ट तौर गार्डनर नामक दो फ्रांसीसी जनरलों को बनाया गया।

(2) **फौज-ए-बेकवायद :-** फौज-ए-बेकवायद मुख्यतः घुड़सवार सेनाएं थी, जो दो भागों में विभाजित थी।

- (A) **घुड़चदा खास** :- इसके अन्तर्गत घुड़सवारों को अपना घोड़ा स्वयं लाना पड़ता था, और उसको वेतन राजकोष से दिया जाता था।
- (B) **मिसलदार** :- ये वे घुड़सवार थे, जिनके राज्यों (मिसलो) को रणजीतसिंह ने अपने राज्य में मिला लिया, था और वे अपनी घुड़सवार सेना के साथ उसकी सेना में सम्मिलित हो गये थे।
- (D) **भू- राजस्व पद्धति** :- रणजीत सिंह के द्वारा जे भूराजस्व पद्धति लागू की गई थी, उसके अन्तर्गत उसने 1823 AD तक बँटाई पद्धति (गल्ला-बक्शी) और उसके बाद अर्थात् 1823 AD के बाद गल्ला-बक्शी की जगह पर कनकूत, पद्धति को अपनाई गई।

कनकूत पद्धति के अन्तर्गत खड़ी फसल पर ही भूमि कर नगदी के रूप में लागू कर दिया जाता था। भूमि-कर की दर उपज का $1/3$ से लेकर $2/5$ या 40% तक थी।

न्याय-व्यवस्था

- रणजीत सिंह के समय में अदालत-ए-आला सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष न्यायधीश होता था। राज्य का उच्च न्यायालय लाहौर में था इसका सर्वोच्च न्यायधीश रणजीत सिंह स्वयं था।
- प्रांतों में नाजिम और जिलों में कारदारों को ही न्यायिक अधिकार प्रदान थे।

रणजीतसिंह के बाद आंग्ल-सिक्ख सम्बन्ध (1839-49)

- रणजीत सिंह की मृत्यु 21 जून 1839 AD को पक्षाघात के कारण हो गई, मृत्यु के बाद उसके तीन उत्तराधिकारी (1) खड़ग सिंह (1839-40) (2) शेरसिंह (1841-43) (3) दलीपसिंह (1843-49) पंजाब की गद्दी पर बैठे।
- रणजीतसिंह के ये तीनों उत्तराधिकारी पूर्णतया अयोग्य और दुर्बल थे। जिसके फलस्वरूप पंजाब में सिक्ख और डोगरा सरदारों की प्रति उदासीनता

काफी बढ़ गई थी। और ये दोनों गुट दरबार में अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये एक दूसरे के विरुद्ध षड़यंत्र रचने लगे।

- सिख शासकों की कमजोरी और सिक्ख तथा डोगरा सरदारों के पारस्परिक संघर्ष के कारण पंजाब में सिक्ख सेना का प्रभाव काफी बढ़ गया था। और सिक्ख सेना अपने शासकों और सरदारों के आदेशों को न मानकर अपने लिये अलग से खालसा पंचायत स्थापित करली, जिसके आदेश पर ही सेना कार्य करती थी।
- रणजीत सिंह के इन दुर्बल उत्तराधिकारियों और सिख सरदारों तथा डोगरा सरदारों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्वता का लाभ उठाकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया गया, उसके फलस्वरूप अंग्रेजों और सिक्खों के बीच निम्नलिखित दो आंग्ल-सिक्ख युद्ध लड़े गये।

प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध / First Angle sikh war (1845-46)

- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के पद पर था, जबकी दलीप सिंह पंजाब का शासक था।
- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध का मुख्य कारण सिख सरदारों की स्वार्थ परता और उसके फलस्वरूप अंग्रेजों का पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था।
- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के दौरान अग्रांकित पांच लड़ाईयाँ लड़ी गई।
- 1846-46 सिक्खों सरदारों की स्वार्थ परता व अंग्रेजों ग्रंथ जॉब में हस्तक्षेप
 1. मुदकी का युद्ध 18 दिस. 1845 AD
 2. फीरोजशाह या फीरुशाह की लड़ाई 21 दिसम्बर 18
 3. बहोवाल की लड़ाई 21 जनवरी, 1846
 4. आलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी, 1846

5. सबराओं का युद्ध 10 फरवरी, 1846

उपरोक्त पांच युद्धों में केवल बुद्धोवल के युद्ध में सिख सेना की विजय हुई, बाकी चारों युद्धों में अंग्रेज विजय हुये थे।

और प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध की सबसे प्रमुख और निर्णायक लड़ाई सबराओं की लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेजों की बहुत ही कठिन संघर्ष और सिख सेना के सेनानायकों लालसिंह और तेजसिंह द्वारा किये गये विश्वासघात के कारण ही विजय हुई थी। इस युद्ध में हारने के साथ ही सिख सेना ने समर्पण कर दिया था।

- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद सिख शासक दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सिख राज्य को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से काफी हद तक दुर्बल बना दिया गया।

लाहौर की संधि कब, किनके मध्य और महत्व स्पष्ट कीजिये।

- लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 AD में सिख शासक दलीपसिंह और अंग्रेजों के बीच (लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल) हुई थी, जिसके मुख्य प्रावधान अग्रलिखित थे।
 - (1) अंग्रेजों द्वारा दलीप सिंह को पंजाब का शासक, उसकी माँ रानी जिंदन को दलीपसिंह का संरक्षक और लालसिंह को वजीर स्वीकार कर लिया गया।
 - (2) दलीप सिंह द्वारा डेढ़ करोड़ रुपया (1½ करोड़ रुपये) युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को दिया जाएगा। जिसके बदले में उसने कश्मीर और हजारा के प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिया।
 - (3) सिखों के तोपखाने पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया।
 - (4) सिख सेना की संख्या घटाकर 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना कर दी गई।

- (5) सतलज नदी के पूर्व में स्थित जो प्रदेश सिखों के अधिकार में थे वे दलीप सिंह द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिये गये।

पंजाब में एक ब्रिटिश रेजीडेंट की नियुक्ति कर दी गई।

महत्व :- इस प्रकार लाहौर की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा दलीप सिंह को आर्थिक व सैनिक दृष्टि से काफी दुर्बल बना दिया।

For Prelime :- दलीप सिंह द्वारा हजारा और कश्मीर के जो प्रदेश लाहौर की संधि के अन्तर्गत जो अंग्रेजों को दिये गये थे, बाद में अंग्रेजों ने कश्मीर 50 लाख रुपये में डोगरा सरदार गुलाब सिंह को बेच दिया। और उसे ही कश्मीर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया था।

- बाद में लालसिंह और रानी जिंदन के द्वारा गुलाबसिंह के विरुद्ध कश्मीर में जो विद्रोह भड़का दिया गया था, उसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने रानी जिंदन और लालसिंह को अपने-अपने पदों से हटा दिया गया, और दलीपसिंह को अंग्रेजों के साथ 22 दिसम्बर 1846 AD को भैरोंवाल की संधि के नाम से एक और संधि करने पर विवश किया, जिसके फलस्वरूप बाद में पंजाब के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश रेजीडेंट के माध्यम से अंग्रेजों का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया।

भैरोंवाल की संधि कब, किनके मध्य और महत्व बताइये।

भैरोंवाल की संधि दिसम्बर 1846 AD में सिख शासक दलीपसिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसके मुख्य प्रावधान अग्रांकित हैं – (1) 8 सरदारों की संरक्षक परिषद बनाई (2) रानी जिन्दल को पैर लाख से (3) वहा सहायक सेना रखी 20 लाख रुपये वार्षिक खर्चों देगे।

1. ब्रिटिश रेजीडेंट सरहेजरी लारेन्स की अध्यक्षता में दलीप सिंह की मदद के लिये आठ सिख सरदारों की एक संरक्षक परिषद नियुक्त कर दी गई थी।
2. रानी जिंदन को दलीप सिंह के संरक्षक पद से हटा दिया गया, उसकी पेशन 1½ लाख रुपये वार्षिक निर्धारित कर दी गई।

3. दलीप सिंह की मदद के लिये एक अंग्रेजी सहायक सेना पंजाब में नियुक्त कर दी गई, जिसके खर्चे के बदले में दलीपसिंह द्वारा 20 लाख रुपये वार्षिक अंग्रेजों को दिये जाएंगे।

महत्व :- भैरोवास की संधि के फलस्वरूप बाद में ब्रिटिश रेजीडेंट के माध्यम से पंजाब के आंतरिक प्रशासन पर भी अंग्रेजों का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया।

द्वितीय आंग्ल सिक्ख वार, 1848–49

द्वितीय आंग्ल-सिक्ख युद्ध के दौरान लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था, तथा दलीप सिंह पंजाब का शासक था।

II आंग्ल-सिक्ख युद्ध का सबसे मुख्य तात्कालिक कारण मुल्तान के गवर्नर (नाजिम) मूलराज द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देना।

मूलराज के विद्रोह का कारण यह था कि जब मूलराज ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा मांगी गई धनराशी देने से इनकार कर दिया था, तब डलहौजी ने मूलराज को हटाकर उसकी जगह पर खानसिंह मान को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, और जिन दो ब्रिटिश अधिकारियों एण्डरसन और एगन्यू की उपस्थिति में मूलराज ने खानसिंहमान के मुल्तान के गवर्नर का पद भार सौंपा था। उन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों की उसी दिन सिक्ख सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई। जिसका आरोप डलहौजी ने मूलराज पर लगाकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, अतः अपनी आत्मरक्षा के लिये मूलराज ने विद्रोह किया था।

- डलहौजी ने मूलराज के इस विद्रोह को दबाने की बजाय पंजाब के अन्य भागों में भी फैल जाने दिया, और अंत में इस विद्रोह को दबाने का बहाना लेकर डलहौजी ने पंजाब में जो सैनिक कार्यवाही की उसी के फलस्वरूप यह II आंग्ल सिक्ख युद्ध प्रारंभ हुआ।
- इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का सेनापति जनरल गफ और बाद में चार्ल्स नेपीयर था, जबकि सिक्ख सेना का कमांडर शेरसिंह था।
- II जनरल गफ/चार्ल्स नेपीयर शेरसिंह इस आंग्ल-सिक्ख युद्ध के दौरान तीन प्रमुख लड़ाईयाँ लड़ी गई।

(1) रामनगर का युद्ध

(2) चिलिमानवाला क युद्ध

(3) गुजरात का युद्ध

- प्रथम दो लड़ाईयाँ अनिर्णायक रही थी, किंतु बाद में डलहौजी ने जनरल लॉर्ड ह्यू गफ की जगह पर को ब्रिटिश सेना का कमांडर नियुक्त किया था, और अंत में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा फरवरी 1849 AD में लड़े गये गुजरात के युद्ध में शेरसिंह के नेतृत्व में सिक्ख सेना को पराजित कर दिया गया। और इसके साथ ही सिंख सेना ने समर्पण कर दिया।
- अंत में मार्च 1849 AD में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया।
- मार्च 1849 डलहौजी पंजाब विलय